ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/324168340

□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□

Research · November 2016

CITATIONS
0

1 author:

Bhagawati Paraksh Sharma
Pacific University India
268 PUBLICATIONS **0** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Bhagawati Paraksh Sharma on 03 April 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

चीन का गहराता संकट और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार

पूरी चीनी अर्थव्यवस्था आज उसके घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत ऋण के बोझ तले चरमराने को है। इन भारी ऋणों के बोझ से दबी कंपनियों के साथ ही चीन के सारे बैंकों सहित उसका मुद्रा तंत्र, उद्योग व वाणिज्य सब कुछ डूब सकता है। – **प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा**

चीन, आज संपूर्ण विश्व में स्थायी शांति, मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद के उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण एवं सामरिक संतुलन लिये गंभीर चुनौती बना हुआ है। लेकिन, आज वह स्वयं एक गंभीर आर्थिक व वित्तीय ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है। वर्ष 2008 में अमेरिकी मेल्ट डाउन से अधिक भयावह मेल्ट डाउन अर्थात आर्थिक संकट वहां मुंह बाये उसे निगलने को खड़ा है। आज कंपनियां 180 खरब डालर अर्थात 18 ट्रिलियन डालर (12060 खरब अर्थात 1206 लाख करोड़ रूपये तुल्य) कर्ज में डूबी हुयी हैं। यह राशि उनके सकल घरेलू उत्पाद की 170 प्रतिशत है। पूरी चीनी अर्थव्यवस्था आज उसके घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत ऋण के बोझ तले चरमराने को है। इन भारी ऋणों के बोझ से दबी कंपनियों के साथ ही चीन के सारे बैंकों सहित उसका मुद्रा तंत्र, उद्योग व वाणिज्य सब कुछ डूब सकता है। यदि अगले एक वर्ष और चीनी उत्पादों की बिक्री घटती रही, यह होना ही है। लेकिन यदि हम जो चीनी वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें खरीदना हमने जारी रखा और चीनी उद्यम बच गए, तो चीनी अर्थव्यवस्था इस पूरे संकट से अत्यंत सहजता से पार पा जायेगी, थोड़ा समय और चीनी माल ही रहा तो। चीन ने इस पूरे संकट से पार पाने की योजना की घोषणा भी 10 अक्टूबर 2016 को कर ही दी है। अब वह उसकी कुछ अकुशल कंपनियों को अपनी मौत मर जाने देगा और कुशल कंपनियां, जिनके उत्पाद विश्व भर में बिकते हैं, उनके ऋण को पूंजी में बदल देगा। कंपनी को ऋण पर ब्याज चुकाना होता है और किश्त भी प्रतिमाह चुकानी होती है। लेकिन इस नवीन प्रस्ताव के अनुरूप उस ऋण को पूंजी में बदलते ही (debt-equity

swap) कंपनी पर से किश्त व ब्याज के भुगतान का दायित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे में आज की मंदी में भी वह कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाने पर भी जीवित रह सकती है, क्योंकि उसे अब न तो किश्त चुकानी है और न ही ब्याज। लेकिन यदि तब भी उसकी बिक्री नहीं हुयी तो उसे (कंपनी को) बंद होना ही है। यदि चीनी माल का हमने पूर्ण बहिष्कार कर दिया और विश्व में भी हमने चीन की पर्यावरणक्षरण, मानवाधिकार हनन, आतंकवाद का संपोषण एवं विश्व शांति के संबंध में खड़ी की जा रही चुनौतियों का स्मरण कराकर सोशल मीडिया पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आवाहन करें तो अधिकांश चीनी कंपनियां बंद होनी ही है। ऋण को पूंजी में बदलने के बाद भी बंद होगी। ऐसे में चीन के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 170 प्रतिशत तक पहुंच चुके कंपनी ऋणों का दो तिहाई अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद तुल्य 120 खरब डालर (12 ट्रिलियन डॉलर) का डूबना तो निश्चित ही है। चीन में कुल बकाया ऋणों की राशि तो आज 280 खरब डालर अर्थात (28 ट्रिलियन डालर) अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यह राशि अमरीका व जापान के संयुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र के तुल्य है। यदि वर्तमान में चीन ने अपनी कंपनी ऋणों की पुनर्रचना, जिसमें ऋणों को पूंजी में परिवर्तन भी सम्मिलित है, के सहारे अपने बैंकिंग तंत्र व बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के उत्पादन तंत्र को बचा लिया तो वह 3–5 वर्ष में अमरीकी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ विश्व की क्रमांक एक की आर्थिक शक्ति व सामरिक शक्ति बन कर खड़ा होगा।

दूसरी ओर अभी जब चीन की अधिकांश कंपनियां व संपूर्ण बैंकिंग तंत्र चरमराने को है। ऐसे में यदि हम चीनी वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे व विश्व में भी ऐसा ही आवाहन करें तो उसका उत्पादन तंत्र व बैंकिंग तंत्र ध्वस्त होगा, निर्यात घटेंगे, विदेशी व्यापार में घाटा भी होगा, विदेशी मुद्रा भण्डार चुक जायेंगे और विश्व चैन की सांस लेगा। भारत का निकट पड़ोसी होने से चीन का सबल होना, भारत के लिये सर्वाधिक संकट कारक होगा।

चीन में कुल बकाया ऋणों की राशि आज 280 खरब डालर अर्थात (28 ट्रिलियन डालर) अर्थात उसके सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक पहुंच गयी है। यह राशि अमरीका व जापान के संयुक्त वाणिज्यिक बैंकिंग तंत्र के तुल्य है।

आज चीन की सर्वाधिक शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियां भारत के विरूद्ध है। हाल ही में उसने अरूणाचल व उत्तराखण्ड में भारत की सीमा में हमारे नहरों व सड़कों आदि के निर्माण आदि कई कार्यों को बाधित किया है। वर्ष में 300–400 बार वह सीमा का अतिक्रमण करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के मामलों में भारत के प्रस्तावों के विरूद्ध वीटो का उपयोग कर रहा है। आणविक आपूर्ति समूह (Nuclear Suppliers Group) में भारत के प्रवेश का विरोध किया है। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के विरोध के बाद भी व्यापक स्तर पर निर्माण कर वहीं से 46 अरब डालर के चीन–पाक आर्थिक गलियारे का विकास कर रहा है। भारत में जल संकट उत्पन्न करने के लिये ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक रहा है। सिंधु नदी का अतिरिक्त जल हम पाकिस्तान में जाने दें इसके लिये धमकियां दे रहा है। हाल ही में नवंबर 3, 2016 को अरूणाचल में सीमा से 29 किमी अंदर हमारा नहर निर्माण का कार्य रूकवाने का दुस्साहस किया है। वर्ष 2016 के कुछ प्रमुख सीमा अतिक्रमणों जिनका यहां उल्लेख किया जा रहा है वही चीन की भारत विरोधी गतिविधियों का आभास करा देते हैं–

1. **नवंबर 3, 2016 को अरूणाचल में भारतीय सीमा में नहर निर्माण में बाधा डालना:** चीनी सैनिकों ने बुधवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) के करीब भारतीय इलाके में चल रहे एक नहर के निर्माण को रुकवा दिया।

भारत के भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 70 और चीन के 55 सैनिक कई घंटे तक आमने–सामने रहे। इस बीच, इंडियन एयरफोर्स को अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा से 29 किलोमीटर नजदीक अपने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट सी–17 ग्लोबमास्टर को उतारना पड़ा। ग्लोबमास्टर को 6200 फीट की ऊंचाई

पर सिर्फ 4200 फीट लंबे इलाके में उतरना पड़ा। वहां चीनी सैनिकों ने यहां तक कह दिया कि भारत को लद्दाख में LAC के पास कंस्ट्रक्शन से पहले चीन से अनुमति लेनी चाहिए थी।

बुधवार की इस घटना में दोनों देशों के सैनिकों ने फ्लैग लगाकर पोजिशन तक ले ली थी। लेकिन, भारतीय जवानों ने भी चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी प्रकार 19 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली में भी चीनी सैनिक नहर का काम रुकवा चुके हैं। तब भी भारतीय जवानों ने उन्हें वापस भेज दिया था। वर्ष 2014 में भी लद्दाख के निलुंग नाले का काम चीनी सैनिकों ने रुकवाकर मजदूरों के टेंटों को नुकसान पहुंचाया था।

2. अरूणाचल में सितंबर 9, 2016 घुसपैठः चीन पहले भारतीय सीमा में स्थानीय लोगों को आतंकित कर पलायन को विवश करता है। उसके बाद ऐसे निर्जन क्षेत्रों में घुसपैठ कर वहां अपने सुरक्षा बलों के अस्थायी कैम्प बना लेता है। ऐसी ही उसने अभी अरूणाचल प्रदेश के अन्जा जिले की प्लम चौकी तक एक निर्जन क्षेत्र में सीमा पार 45 किमी भारतीय सीमा में घुसकर अस्थायी कैम्प व आशियाने भी बना लिये। सीमा में इतनी गहराई तक आने के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र खाली करने को कहने पर इस क्षेत्र को अपना (चीनीयों का) बताया। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चीनी सैनिकों को अत्यंत कड़ा रूख अपनाने पर 4 दिन बाद 13 जून को उस क्षेत्र को खाली किया।

चीन वर्ष में कुल 300– 400 बार तक घुसपैठ कर लेता है। अनेक क्षेत्रों में वह इंच दर इंच करके कई क्षेत्रों में स्थायी रूप से भी आगे बढ़ रहा है।

3. जून 10, 2016 को 250 सैनिकों की घुसपैठः अरूणाचल प्रदेश के ही कामेंग जिले के यागत्से क्षेत्र में जून 10, 2016 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 250 जवानों ने घुसपैठ की। वहां सीमा क्षेत्र में गश्त का काम चीनी बोर्डर गार्ड्स का है, चीनी सैनिकों का वहां आना सुनियोजित घुसपैठ ही कही जा सकती है। भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा कड़ा रूख अपनाने के बाद ही वे लौटे हैं। इसी अवधि में चीन ने 48 सदस्यीय आणविक आपूर्ति समूह में प्रवेश के विरोध में भी लगा हुआ था।

4. मार्च 8, 2016 को फिंगर VIII–सिरजेप–I से 5.5 किमी घुसपैठः इसी प्रकार के लेह लद्दाख क्षेत्र की ओर भार ठाकुग चौकी से 5.5 किमी अंदर तक चार वाहनों व भारी शस्त्रास्त्रों साथ चीनी प्लाटून ने घुसपैठ करके भारतीय बलों पर भारी दबाव उत्पन्न किया। इनमें एक कर्नल व दो मेजर टेंक के अधिकारी दो हल्के वाहन एक मध्यम व एक भारी वाहन था। यह क्षेत्र पेगांग झील के पास पड़ता है, जहां वे आये दिन तनाव पैदा करते रहते हैं।

5. जुलाई 2016 में उत्तराखण्ड में घुसपैठः चीनी सैनिकों ने उत्तराखण्ड के चमोली जिले के बारहोती क्षेत्र में 80 वर्ग किमी के चारागाह क्षेत्र में घुसपैठ कर वहां भी तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया। चीन के साथ तनाव न हो, इसलिये वहां भारतीय सुरक्षा बल बिना शस्त्र व बिना गणवेश के ही गश्त करत हैं। वैसे भारत को इतना संकुचित व सिमटा रहना भी उचित नहीं है। इस क्षेत्र में चीन ने 2013 व 2014 में भी कई बार घुसपैठ की है और हमारी वायु सीमा का भी अतिक्रमण किया है।

इस प्रकार चीन वर्ष में कुल 300–400 बार तक घुसपैठ कर लेता है। अनेक क्षेत्रों में वह इंच दर इंच करके कई क्षेत्रों में स्थायी रूप से भी आगे बढ़ रहा है। ऐसी घुसपैठों व दौलत बैग ओल्डी में 21 दिन तक रहकर भारत की ब्लेकमेलिंग की समीक्षा लेखक ने अपनी तीन अन्य पुस्तकों में किया है।

भारत के सीमा क्षेत्र में विकास की आवश्यकताः चीन ने पूरी 4057

किमी लम्बी भारत तिब्बत सीमा पर अत्यंत व्यवस्थित सड़कें रेलमार्ग, विद्युतीकरण व संचार साधनों का विकास कर लिया है। वह जब चाहे बड़े पैमाने पर सैन्य बल जमा कर सकता है। लेकिन अब वह भारतीय सीमा में किसी भी प्रकार की गतिविधी या हलचल होने पर वह अडंगा लगा देता है। इसलिये वहां के ग्रामीणों को भारी असुविधा होती है। सर्दी में रास्तों से बर्फ हटाने तक की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीण परेशानी में पलायन करने तक को विवश हो जाते हैं। चीन चाहता है इन सबसे चीन वहां के निवासियों को बताना चाहता है कि यहां वे अपने क्षेत्र में चीन का स्वागत करे तो ही उनके वहां सारी नागरिक सुविधायें विकसित होगी। इसलिये भारत को सीमा क्षेत्र में सब प्रकार की अवसरंचना व नागरिक सुविधायें द्रुत गति से विकसित करनी चाहिये। साथ ही चीन के उपरोक्त वर्णित आर्थिक संकट के आलोक में उसे सही पाठ पढ़ाने के लिये चीनी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार भी कर देना चाहिये।

चीन का आर्थिक सशक्तिकरण अनुचितः चीनी वस्तुओं की खरीद से चीन का आर्थिक व सामरिक सशक्तिकरण भारत के लिये सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण होगा और हमें अपने संसाधन विकास के स्थान पर चीन–पाक से सुरक्षा में लगाने होंगे। इसके लिये भारत को अपने अबाध विकास के लिये चीन पर आर्थिक अंकुश लगाना सर्वाधिक आवश्यक है। चीन द्वारा की जा रही अनवरत शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के उपरांत भी, भारत द्वारा चीन को सर्वाधिक व्यापार सुविधाएं देना और भी आत्मघाती कदम है। देश का सर्वाधिक 51 अरब डालर (3.5 लाख करोड़ रूपयों) का व्यापार घाटा, आज केवल चीन के साथ ही है। चीन से घोषित रूप में 4.25 लाख करोड़ रूपये व बड़ी मात्रा में अघोषित व कम बिल का माल भी देश में आ रहा है। आज देश में 5–6 लाख करोड़ रूपये का माल देश में आ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि चीन का जो आज देश में हम 5–6 लाख करोड़ रूपये का माल आयात करते हैं, उसे हमें तत्काल बंद करना चाहिये। देश की जनता आज चीनी माल खरीदना बंद कर दे, यह चीन के प्रति हमारा सर्वोत्तम कदम सिद्ध होगा। अतएवं आज जब चीन एक आर्थिक, वित्तीय, बैंकिंग व कार्पोरेट संकट के ज्वालामुखी पर बैठा है, चीनी वस्तुओं का परित्याग ही इस संकट में विस्फोट की संभावना निश्चित करेगा। इससे चीन की संपूर्ण विश्व के लिए संकट उपजाने वाली गतिविधियों पर भी अंकुश लग सकेगा एवं विश्वभर में फैलते पर्यावरण संकट, विश्व के विभिन्न भागों में मानवाधिकारों के हनन और आतंकवाद पर नियंत्रण संभव होने से संपूर्ण विश्व की मानवता राहत की सांस लेगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)**
में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

View publication stats